



स्वास-खबर

अभिषेक की साली और ममता कैबिनेट में शिक्षा मंत्री को सीबीआई का नोटिस

कोलकाता (एजेंसी)। (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का दौर 27 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बीच सीबीआई ने तुणमूल कांग्रेस के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार और बंगाल के शिक्षा मंत्री को नोटिस भेजा है। दोनों को अलग-अलग मामलों में समन जारी किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने पांजी घोटाळा मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को तलब किया है। सीबीआई के अधिकारी ने यह जानकारी दी है। वहीं, अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार मेनका गंभीर के परिवार के दो सदस्यों को उस करोड़ों रुपये के कोयला चोरी मामले के सिलसिले में शुक्रवार को समन जारी किये जिसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है।

मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ने से किया इनकार

कोलकाता (एजेंसी)। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी मिथुन चक्रवर्ती से बात हुई थी उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। अगर पार्टी निर्णय करेगी तो हम मिथुन दा से बात करेंगे और अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में गोरखा आंदोलन को कुचलने के लिए पहले सीपीएम ने 1000-1200 लोगों को हत्या की थी और पिछले दिनों टीएमसी ने लगभग 12-13 लोगों की हत्या की। हम ये वादा करते हैं ये अवसर अब कभी नहीं आएगा।

महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड मामले बढ़े

नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन, पुणे में नाइट कर्फ्यू

मुंबई (एजेंसी)। कोरोना वायरस की नई लहर से महाराष्ट्र का बुरा हाल होता दिख रहा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र कोरोना की रडार पर है और यहां मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि धीरे-धीरे अब महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन के खतरे मंडराने लगे हैं। नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है।

अकोला में 15 मार्च तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं, पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अकोला में शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं, पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 31 मार्च तक स्कूल और कालेजों को बंद कर दिया गया है। साथ ही होटलों और बार को आदेश दे दिया गया है कि वे रात दस बजे के बाद



नहीं खोले रखेंगे। अब महाराष्ट्र में के अन्य इलाकों में भी लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र की स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकोला से पहले नागपुर में एक सप्ताह (15 से 21 मार्च) का लॉकडाउन लगाया गया है। इतना ही नहीं, ठाणे में भी करीब 16 हाटस्पॉट में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा (शेष पेज 2 पर)

देश में एक दिन में कोविड के 23,285 नए मामले

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 23,285 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या अब 1,13,08,846 हो गई। आंकड़ों के अनुसार, पिछले 78 दिनों में सामने आए ये सर्वाधिक नए मामले हैं। इससे पहले, 24 दिसंबर को एक दिन में 24,712 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 117 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या अब 1,58,306 हो गई। देश में अभी 1,97,237 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.74 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल 1,09,53,303 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 96.86 प्रतिशत है। वहीं, कोविड-19 से मृत्यु दर 1.40 प्रतिशत है। देश में पिछले साल सात अगस्त में संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को (शेष पेज 2 पर)

मद्र में संक्रमण तेजी से फैलना शुरू, इंदौर में 219 व भोपाल में 138 पॉजिटिव केस

भोपाल (काप्र)। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण एक फिर तेजी से फैलना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में 603 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दो माह पहले यानी 10 जनवरी को 620 केस मिले थे। इसके बाद कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी हो रही थी। लेकिन मार्च माह में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस इंदौर और भोपाल में मिल रहे हैं। 2021 में सबसे ज्यादा केस एक दिन में 11 मार्च को इंदौर में 219 व भोपाल में 138 केस मिले। 31 दिसंबर को इंदौर में 219 व भोपाल में 147 लोग पॉजिटिव आए थे। हालांकि 10 जनवरी को भोपाल में 169 केस मिले थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पॉजिटिव रेट भी 4 फीसदी हो गया है, जो अच्छे संकेत नहीं है। 11 मार्च को 14,378 टेस्ट हुए, जिसमें से 603 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान इंदौर और छिंदवाड़ा में एक-एक मरीज की मौत भी हुई है। कोरोना के आंकड़े देखें तो एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या मात्र 17 दिन में दो गुना हो गई है। मध्य प्रदेश में 23 फरवरी को एक्टिव केस 2151 थे, जो 11 मार्च को बढ़ कर 4335 हो गए हैं। इंदौर (शेष पेज 2 पर)

प्रधानमंत्री ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' की शुरुआत की

अहमदाबाद (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का 'अमृत महोत्सव' समारोह की शुरुआत की। मोदी ने बताया कि 75वीं वर्षगांठ का समारोह 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तर्ज पर गुजरात के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 81 लोगों ने पदयात्रा शुरू की जो 386 किमी दूर नवसारी के दांडी तक जाएगी। 25 दिन की इस पदयात्रा का समापन पांच अप्रैल को होगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की घोषणा करते हुए 78 लोगों ने 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू की थी। अहमदाबाद हवाईअड्डे पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से साबरमती आश्रम पहुंचे जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वह आश्रम में स्थित आवास हृदयकुंज भी गए जहां गांधी 1918 से 1930 तक अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ रहे थे। मोदी ने आंगतुक पुस्तिका में लिखा कि यह महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने आगे लिखा- साबरमती आश्रम आकर और बापू की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण का मेरा दृढ़ निश्चय और भी मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने लिखा, महात्मा गांधी ने आत्म निर्भरता और आत्म विश्वास का संदेश यहीं से दिया था। उन्होंने लिखा कि आजादी का



अमृत महोत्सव हमारे लोगों द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वाधीनता (शेष पेज 2 पर)

हम क्वांट देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे: मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

क्वांट के चारों सदस्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की शुरुआत को पहली बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वांट समिट के शुरुआती संबोधन में कहा कि भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम के विस्तार को

वह सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। हम परस्पर सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम साझा मूल्यों के साथ धर्मनिरपेक्ष, स्थिर और समृद्ध हिन्दू-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बैठक के बाद बताया, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी दुनिया के कल्याण के लिए है। आज का

सम्मेलन दिखाता है कि क्वांट नेताओं ने सकारात्मक एजेंडा और दृष्टिकोण अपनाया है। वैक्सिन, क्लाइमेट चेंज और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे समकालीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। क्वांट वैक्सिन की पहली बेहद महत्वपूर्ण है। हम वैक्सिन पर शोध-विकास, उत्पादन और फंडिंग के लिए मिलकर काम करेंगे। हिन्दू प्रशांत क्षेत्र में (शेष पेज 2 पर)

ईसी से टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने कहा ममता का चोटिल होना दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं, बल्कि साजिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। तुणमूल कांग्रेस का छह सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचा। तुणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि दल ने निर्वाचन आयोग से कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंदीग्राम में चोटिल होना दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, बल्कि साजिश है। प्रतिनिधि दल ने निर्वाचन आयोग से घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। तुणमूल कांग्रेस ने नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की साजिश की बात पर जोर देने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा नेताओं के व्हीट और टिप्पणियों के बारे में निर्वाचन आयोग को जानकारी दी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह मुलाकात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तुणमूल (शेष पेज 2 पर)

ममता को मिली अस्पताल से छुट्टी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, डाक्टरों ने कहा कि इलाज के बाद ममता अच्छा रिस्पान्स कर रही थीं। डाक्टरों ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी बार-बार छुट्टी दिए जाने का निवेदन कर रही थीं। इसी वजह से उन्हें कुछ निर्देशों के (शेष पेज 2 पर)

शुभेंदु ने नंदीग्राम सीट से भरा पर्चा



कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट पर वह सीएम ममता बनर्जी के मुकाबले उतर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आए। उनके अलावा बाबुल सुप्रियो और स्मृति इरानी भी उनके समर्थन में पहुंचे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी भगवान की शरण में नजर आए।

नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक

शहरी इलाकों पर खर्च होंगे 44 हजार करोड़

भोपाल (काप्र)। नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। इससे प्रदेश के 407 नगरीय निकायों की तस्वीर बदलने के लिए विकास का रोड मैप तैयार किया है। प्रदेश के शहरी इलाकों के विकास पर सरकार अगले 5 साल में 44000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसकी शुरुआत आज हो गयी।

भोपाल में हुए नगर उदय कार्यक्रम में शिवराज सिंह ने करोड़ों रुपये हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए। नगर उदय कार्यक्रम के तहत ढाई लाख हितग्राहियों को 1602 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। यह पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्व निधि योजना के तहत है। इसके अलावा सरकार शहरी इलाकों की सड़कों के लिए 1331.25 करोड़ रुपये दे रही है। सरकार का दावा है कि सड़कों के निर्माण के लिए को 59 करोड़ की राशि नगरीय निकायों को पहले ही दे चुकी है। आज 660 करोड़ रुपये और दिये जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार जल्दी 299 करोड़ रुपये और देगी। ये पैसे से शहरी इलाकों में पेयजल, सफाई और प्रदूषण कंट्रोल पर खर्च किए जाएंगे।

नारियल फोड़ने का खेल शुरू: निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार के नगर उदय



- कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा निकाय चुनाव की घोषणा की आहत से पहले शिवराज सरकार मिशन नगर उदय के नाम पर एक बार फिर झूठे नारियल फोड़ने की तैयारी में है। जो हर चुनाव के पहले फोड़े जाते हैं। कमलनाथ ने कहा सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है। गुमराह करने वाली झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोस कर जनता को गुमराह करने का खेल शुरू हो गया है। उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल उठाया कि प्रदेश में बीते 15 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। लेकिन 15 साल के बाद अब शहरी इलाकों के विकास का रोड मैप सरकार बना कर रही है।
- अलग अलग योजनाओं के तहत 3 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर।
- पीएम आवास योजना के तहत 1।60 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 1602 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर।
- 15वें वित्त आयोग की 810 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर।
- मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के 500 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास।
- नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए 100 करोड़ की राशि का वितरण।
- निकायों के पंचवर्षीय विकास के रोडमैप का विमोचन।

जबकि अब तक तो प्रदेश के सभी नगरीय निकाय सर्वश्रेष्ठ हो जाने चाहिए थे। कोरोना काल में विकास का दावा: कमलनाथ के ट्वीट पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कोरोना काल में शहरी विकास के लिए करोड़ों रुपये देना अपने आप में बड़ा फैसला है। सरकार के इस कदम से शहरी इलाकों में जरूरी विकास के काम हो पाएंगे। इस वजह से इन दलों से दूरी बना कर रखेंगे। छोटे और स्थानीय दलों को आगामी चुनाव में तरजीह देंगे। भाजपा से नाता रखने वाले दलों से भी उन्होंने दूर रहने को कहा। उनसे जब यह सवाल किया गया कि क्या अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा से भी गठबंधन करेंगे तो उनका जवाब था वह भी छोटा दल है।

बड़े दलों से खराब रहा अनुभव, अब छोटे दलों से होगा गठबंधन: अखिलेश

मुरादाबाद (एजेंसी)। सपा अभी से 2002 की तैयारी में जुट गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जिलावार पहुंच कर पार्टी के लोगों से विस्तार से बात कर रहे हैं। बातचीत में सपा सरकार के कामों का हवाला दे रहे हैं। यह भी ऐलान किया है कि अब बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। छोटे दलों के साथ मिल कर चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि जहां सुधार की गुंजाइश होगी वहां करेंगे। बातचीत में उन्होंने यह स्वीकार कि बड़े दलों (कांग्रेस बसपा) के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। इस वजह से इन दलों से दूरी बना कर रखेंगे। छोटे और स्थानीय दलों को आगामी चुनाव में तरजीह देंगे। भाजपा से नाता रखने वाले दलों से भी उन्होंने दूर रहने को कहा। उनसे जब यह सवाल किया गया कि क्या अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा से भी गठबंधन करेंगे तो उनका जवाब था वह भी छोटा दल है।



सीबीआई निदेशक की नियमित नियुक्ति पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एनजीओ की उस याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया है जिसमें नियमित सीबीआई निदेशक को तत्काल नियुक्त करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट को पीठ ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। मामले में अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। %कामना काज% नामक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए वैधानिक कानून के अनुसार एक उचित नियुक्ति आवश्यक है। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में एनजीओ ने तर्क दिया कि सीबीआई निदेशक संगठन में अंतिम प्राधिकारी है। इसलिए, इस माननीय न्यायालय और बाद में संसद ने सीबीआई निदेशक को कार्यात्मक स्वायत्तता को बढ़ाने और इस प्रमुख कार्यकारी को नियुक्ति के मामले में कार्यकारी विवेक की सीमा को सीमित करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं।

स्पेशल खबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी अधिकारी को...

राज्य चुनाव आयुक्त बनाना संविधान का मजाक

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट रखना है।



शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकारी अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त का अडिशनल चार्ज देना तो संविधान के साथ मजाक है। जस्टिस रोहित नरीमन की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जिसमें उसने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमतर करना

स्वीकार्य नहीं हो सकता और राज्य चुनाव आयुक्तों के लिए स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए। गोवा के ला सेक्रेटरी को वहां का चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। इसी मामले में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं हो सकता है। सरकारी पद पर बैठे किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त का चार्ज देना संविधान का मजाक उड़ाना है। सुप्रीम

कोर्ट ने कहा कि नगरपालिका परिषद चुनाव के लिए राज्य सरकार की तरफ से अपने ला सेक्रेटरी को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करना सही है। अदालत ने कहा कि ये बेहद परेशानी पैदा करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार की नौकरि करने वाला या उससे जुड़ा शख्स राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर काम नहीं कर सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र शख्स होना चाहिए, वह सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता। इस बात हाई कोर्ट ने गोवा पंचायत चुनाव में व्यवस्था दी थी जिसके खिलाफ गोवा सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी।